

प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
16.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

एमओयू

प्रदेश में डेयरी उत्पाद क्षेत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने आज शिमला में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ 3 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में हुए इन समझौता ज्ञापनों के तहत कांगड़ा जिला के ढगवार में सितंबर माह तक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का कार्य पूरा किया जाएगा और इसका संचालन पूरी तरह से एन.डी.डी.बी. करेगा। इसके अलावा नाहन व नालागढ़ में डेयरी प्लांट जबकि जलाड़ी व झलेड़ा में चिलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहल से उत्पादन प्रबंधन, स्टॉक नियंत्रण और सप्लाई चेन की निगरानी अधिक प्रभावी होगी, जिससे डेयरी संचालन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार 3 सौ करोड़ रुपये खर्च करेगी।

सिकंदर कुमार

केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथी चौधरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता के सृजन व विस्तार के लिए 23 दलहन प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी गई हैं, जिनमें से 18 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2026-27 रबी खरीद सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने नेफेड और एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से पहले ही डेढ़ लाख दलहन उत्पादक किसानों को पंजीकृत कर लिया है।

सुरेश कश्यप

केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरणीय स्थितियों का निरंतर अध्ययन किया जा रहा है। लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप द्वारा प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण

नीतिगत और नियामक उपाय लागू किए गए हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है।

पैंशनर

हिमाचल प्रदेश पैंशनर संयुक्त संघर्ष समिति अपनी लंबित देनदारियों को लेकर लगातार आंदोलनरत है। इसी कड़ी में पैंशनरों के विभिन्न संगठनों ने आज शिमला में प्रदर्शन किया। पैंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने बताया कि 21 मार्च को पेश होने वाले बजट में यदि उनकी लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो 30 मार्च को प्रदेशभर से आए पैंशनर विधानसभा का घेराव करेंगे।

मौसम

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रूक-रूक कर बर्फबारी हो रही है। मार्च के महीने में हुई इस वर्षा व बर्फबारी से तापमान में जोरदार गिरावट आई है। जनजातीय ज़िला लाहौल-स्पिति के ताबो में आज न्यूनतम तापमान माईनस 2 दशमलव 5 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। बर्फबारी के कारण रोहतांग पास से कोकसर सड़क सहित ज़िले के अधिकतर मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गए हैं। बर्फबारी के कारण अटल टनल के साऊथ और नॉर्थ पोर्टल के पास फंसे पर्यटकों को मनाली पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षित निकाला जा रहा है।
